GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBE No. /93 /2019

No. E(NG)II/2010/RC-5/1 **New Delhi, dated 11 .11.2019**

To

The General Manager,
All Zonal Railways/ Production Units
(As per standard mailing list)

Sub: Revision of policy regarding compensation of Land losers affected by land acquisition for Railway projects.

Ref: (i) RBE No. 99/2010 dated 16.07.2010
(ii) RBE No. 120/2010 dated 13.08.2010
(iii) Railway Board's letter No. E(NG)II/2010/RC/5/1 dated 28.09.2010.

1. On notification of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 (Removal of Difficulties) Order 2015 dated 28.08.2015, provisions of RFCTLARR Act 2013 related to determination of compensation in accordance with First, Second and Third Schedules of the RFCTLARR Act 2013 have become applicable to all cases of land acquisition under the Railways Act 1989 also. This inter alia means that, irrespective of whether land acquisition for Railway projects is done through Railways Act 1989 after declaring it as a Special Railway Project or through RFCTLARR Act 2013 through State Governments, determination of compensation shall be in accordance with First, Second and Third Schedules of the RFCTLARR Act 2013.

2. The modalities for implementation of Serial No. 4 of the Second schedule of the RFCTLARR Act 2013 were examined by Ministry of Railways and it has been decided that:

i. Ministry of Railways' earlier policy of offering appointment in Railways to affected land-losers issued vide references above is withdrawn and circulars issued in this regard vide reference above stand superseded.

ii. Lump sum payment of Rs. 5 Lakhs to be provided to affected families who were **primarily dependent on acquired land for livelihood,** i.e., cases where their livelihood is affected by such

---2/-

acquisition or where entire land-holding of the affected family have been acquired.

3. Before considering grant of any relief under Second Schedule, however, the Competent Authority for Land Acquisition (CALA) or Collector should unequivocally certify that the affected family has been displaced and dislocated to another area or their entire land holding has been acquired. Further, in case of joint ownership of a plot of land, lump sum payment of Rs. 5 Lakhs should be shared between joint owners of plot in same ratio in which land value is to be shared.

4. This may be brought to the notice of all concerned authorities dealing with the acquisition of land and ensure that all determination of compensation for acquisition of land under the Railways Act, 1989 are in consonance with the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (RFCTLARR) Act, 2013.

5. This policy shall be effective from the date of issue of this letter.

6. This issues with the concurrence of Finance and approval of the Competent Authority.

(Chandra Shekhar)
Jt. Director Land & Amenities
Railway Board

(M. M. RAI)
Jt. Director Estt.(N)II
Railway Board

No. E(NG)II/2010/RC-5/1 **New Delhi, dated 11.11.2019**

Copy to:

(i) The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi (35 spares).
(ii) The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 spares).
(iii) All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
(iv) The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Railway Board (5 spares).
(v) The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers' Association.
(vi) The President, Railway Board Class II Officers' Association.
(vii) The Secretary General, IRPOF.
(viii) The Secretary, Indian Railways Class II Officers' Association.
(ix) The Secretary, Railways Board Ministerial Staff Association.
(x) The President, Railway Board Class IV Officers' Association.

---3/-

(xi) The General Secretary, AIRPF Association.
(xii) The General Secretary, All India SC& ST Railway Employees Association, Room No-7, Rail Bhawan, New Delhi.
(xiii) Chief Commissioner for Railway Safety, Lucknow.
(xiv) Chief Administrative Officer, RCF/Raebareli Project, Kishanganj, Delhi-7

For Secretary/Railway Board

Copy to: PSs to MR and MOS(R)

Copy to: PSO/Sr.PPS/PPSs/PSs/PA to:

CRB, FC, MS, M(RS), ME, M(Tr), MT, M(S&T), M(MM), Secretary/Railway Board, DG(Pers.), DG/RHS, DG/RPF.

AM(Comml), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elect), AM(Budget), AM(ME), AM(Mech), AM(Plg), AM(PU), AM(Tele), AM(Sig), AM(Store), AM(TT), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), AM(F), PED(Vig.), PED(Infra), PED(Transformation).

EDE(N), EDCE(G), EDF(E), ED(IR), ED(Safety), EDV(A), EDE(RRB), EDE(Sports), ED(E&R), EDE(GC), EDE(Res), EDH(P), ED(T&MPP), EDE, EDPC-I & II, EDF(BC), ED (ERP), EDE(G) Chairman/HRRC, JS, JS(G), JS(E), JS(C), DE(N)II, Dir. (MPP), DS(G), DF(E), DE(G), DE(GP), DE(Rep.), JDF(E), JDE(N), JDE(P&A), JDE(GC), JDE(W), JDE(Res)I, JDE(Rep), DE(RRB), DE(LL), DDF(E)I & III, DDE (MPP), DDE (R)-II, DDE (LR)-I ,II & III.

E(P&A)I&II, E(W), E(G), E(NG)I, E(Trg), E(MPP), F(E)I&II, A/C-III, ERB-I, II, III, IV, V & VI, E(Rep)I, II & III, E(Sports), E(W) Sec(E), FE(Spl), E(RRB), PC-III, IV, V & VI, E(SCT)I&II, E(GR) I & II, E(GC), E(GP), PR, E(D&A), E(Co-op), Signal, Tele., Code Revision Cell/ Branches of Railway Board

*****

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/ (RAILWAY BOARD)
*****

आरबीई नं. 193/2019

सं. ई(एनजी)-II/2010/आरसी-5/1

नई दिल्ली, दिनांक: 11/11/2019

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भूमि विस्थापितों को मुआवज़ा देने से संबंधित नीति में संशोधन।

संदर्भ: (i) दिनांक 16.07.2010 का आरबीई सं. 99/2010
(ii) दिनांक 13.08.2010 का आरबीई सं. 120/2010
(iii) रेलवे बोर्ड का दिनांक 28.09.2010 का पत्र सं. ई(एनजी)/2010/आरसी/5/1

1. दिनांक 28.08.2015 के भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश 2015 की अधिसूचना पर आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूची के अनुसार क्षतिपूर्ति के निर्धारण से संबंधित आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधान रेल अधिनियम 1989 के अंतर्गत हुए भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों पर भी लागू हो गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इसका तात्पर्य यह है कि इसका ध्यान किए बिना कि भूमि अधिग्रहण विशेष रेल परियोजना के रूप में घोषित किए जाने के पश्चात् रेल अधिनियम, 1989 के माध्यम से रेल परियोजना के लिए किया गया है अथवा राज्य सरकार द्वारा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के माध्यम से भूमि अधिग्रहण किया गया है, क्षतिपूर्ति का निर्धारण आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूची के अनुसार किया जाएगा।

2. रेल मंत्रालय द्वारा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची के क्रम सं. 4 के क्रियान्वयन के लिए तौर-तरीकों की जांच की गई थी और यह विनिश्चय किया गया है कि:

   i उक्त संदर्भित पत्रों के तहत जारी प्रभावित भूमि विस्थापितों को रेलवे में नियुक्ति की पेशकश करने की रेल मंत्रालय की पूर्व नीति को वापस ले लिया गया है और उक्त संदर्भित पत्रों के तहत इस संबंध में जारी किए गए परिपत्रों का अधिक्रमण होता है।

ii उन प्रभावित परिवारों को 5 लाख रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जाए, जो जीविका के लिए प्राथमिक रूप से अधिगृहीत भूमि पर निर्भर थे अर्थात् ऐसे मामले, जहां उनका जीवन ऐसे भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होता है अथवा जहां प्रभावित परिवार की समस्त भूमि अधिगृहीत की ली गई है।

3. बहरहाल, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत कोई अनुदान प्रदान करने के लिए विचार करने से पूर्व भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) अथवा जिलाधिकारी को स्पष्ट रूप से यह सत्यापित करना चाहिए कि प्रभावित परिवार को विस्थापित किया गया है और वहां से किसी अन्य स्थान पर भेज दिया गया है अथवा उनकी समस्त भूमि को अधिगृहीत कर लिया गया है। इसके अलावा, भूमि पर संयुक्त स्वामित्व के मामले में भूमि के संयुक्त स्वामियों के बीच 5 लाख रुपए के एकमुश्त भुगतान को भूमि के मूल्य के समान अनुपात में बांटा जाना चाहिए।

4. इसे भूमि अधिग्रहण के निपटान से संबंधित सभी प्राधिकारियों के नोटिस में लाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के तहत क्षतिपूर्ति का निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम 2013 के अनुरूप है।

5. यह नीति इस पत्र के जारी होने की तारीख से लागू होगी।

6. इसे वित्त की सहमति और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

चन्द्रशेखर

(चन्द्र शेखर)
संयुक्त निदेशक भूमि एवं सुविधाएं
रेलवे बोर्ड

एम मोहन राय

(एम. एम. राय)
संयुक्त निदेशक स्थापना (एन)-।।
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एनजी)-।।/2010/आरसी-5/1

नई दिल्ली, दिनांक: 11/11/2019

<u>प्रतिलिपि प्रेषित:</u>

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी,एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेलवे बोर्ड (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन।
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास ।। ऑफिसर्स एसोसिएशन।
7. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ।
8. सेक्रेटरी, इंडियन रेलवे क्लास ।। ऑफिसर्स एसोसिएशन।
9. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय कर्मचारी एसोसिएशन।
10. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास IV ऑफिसर्स एसोसिएशन।
11. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरपीएफ एसोसिएशन।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे इंप्लाइज एसोसिएशन, कमरा नं-7, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ
14. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आरसीएफ/रायबरेली परियोजना, किशनगंज, दिल्ली-7

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड